भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2381
जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने हेतु मानदंड/दिशानिर्देश

2381. श्री के. ई. प्रकाश:
श्री डी. एम. कथीर आनंद:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु के वेल्लोर में अनाईकट, के.वी. कुप्पम, वानियमबाड़ी, अम्बुर और गुडियाथम ब्लॉकों सहित तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं और एटीएम की उपलब्धता का कोई खाका तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास बैंक शाखाएं खोलने के लिए दूरी अथवा जनसंख्या संबंधी सीमा के संबंध में कोई निर्धारित मानदंड या दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में कितने नए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खोले गए हैं और उक्त मानदंडों के अंतर्गत कौन-कौन सी बैंक शाखाएं खोली गई हैं;

(घ) सरकार को महाराष्ट्र से धाराशिव जिले के 60 गॉवों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ड.) क्या सरकार बैंकिंग अवसंरचना संबंधी बड़ी कमी को स्वीकार करती है जिसके कारण लोग जन धन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और पीएमजेजेबीवाई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार की डिजिटल खाई को पाटने के लिए इन क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक स्थापित करने या मोबाइल बैंकिंग वैन तैनात करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और बजटीय आवंटन कितना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): सरकार का प्रयास देश में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/ कारोबार प्रतिनिधि/भारतीय डाक भुगतान बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप अर्थात जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप द्वारा बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता की निगरानी की जाती है। जेडीडी ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर देश के कुल 6,01,328 आबादी वाले गांवों में से, 6,00,803 (99.91%) गांव 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा / बीसी / आईपीपीबी) से कवर किए गए हैं। दिनांक 30.06.2025 तक जेडीडी ऐप पर मैप किए गए महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थिति निम्नानुसार है:-

राज्य	बैंक शाखाएं	एटीएम
महाराष्ट्र	7,593	11,604
तमिलनाडु	6,397	13,374

एसएलबीसी, महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि धाराशिव जिले के 60 गांवों में नई बैंक शाखा खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव हाल में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सितंबर 2023 में धाराशिव जिले के 41 स्थानों पर बैंक शाखाएँ खोलने का अनुरोध जिला समाहर्ता, धाराशिव से प्राप्त हुआ था। 41 स्थानों का सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि सभी स्थान पहले से ही एक या अधिक बैंकिंग आउटलेट से कवर थे।

इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) की कोई नई शाखा नहीं खोली गई है। नई बैंक शाखाएं खोलने के प्रस्तावों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, डाक विभाग (डीओपी) ने अवगत कराया है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) डाक विभाग के क्रमश 11,855 और 14,020 डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट के रूप में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। आईपीपीबी डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाएं प्रदान करके सुविधा प्रदान कर रहा है।

*****